मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण

2437. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। रायगढ़, भोपाल, चिरीमिरी, रतलाम, छत्तीसगढ़, रायपुर, कोरबा और नागदा में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें अशोधित/आंशिक रूप से शोधित बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन के कारण प्रतिकूल प्रभावों के बारे में हैं।

(ग) मध्य प्रदेश के 8 शहरों में परिवेशी वायु-गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और विभिन्न कस्बों के 46 केन्द्रों पर जल-गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। सरकार ने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) बहिस्राव और उत्सर्जन के विसर्जन को निर्धारित मानकों के भीतर सीमित रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहा गया है।

(3) परिवेशी वायु-गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों द्वारा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु स्कीम शुरू की गई है।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

Interaction with ONGC for oil drilling

2438. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has ever had any interaction with ONGC on the *minimum safeguards to be undertaken* while drilling for oil;

(b) if so, the details of such discussion;

(c) what was the outcome;

(d) whether there was any consensus between your Ministry and the ONGC on ecological issues; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (e) Yes, Sir. All the proposals of ONGC for environmental clearance are examined by the Ministry as per procedure already laid down. Continuous interaction is being maintained with all the concerned authorities in ONGC for implementation of various safeguards stipulated while environmental clearance are accorded. The environmental clearances are always accorded only after satisfying the ecological issues that are likely to arise during the implementation of project and after production commences.

Environmental havoc of non-degradable plastic materials

2439. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that articles of non-degradable plastic material left as litter, are creating havoc to the